

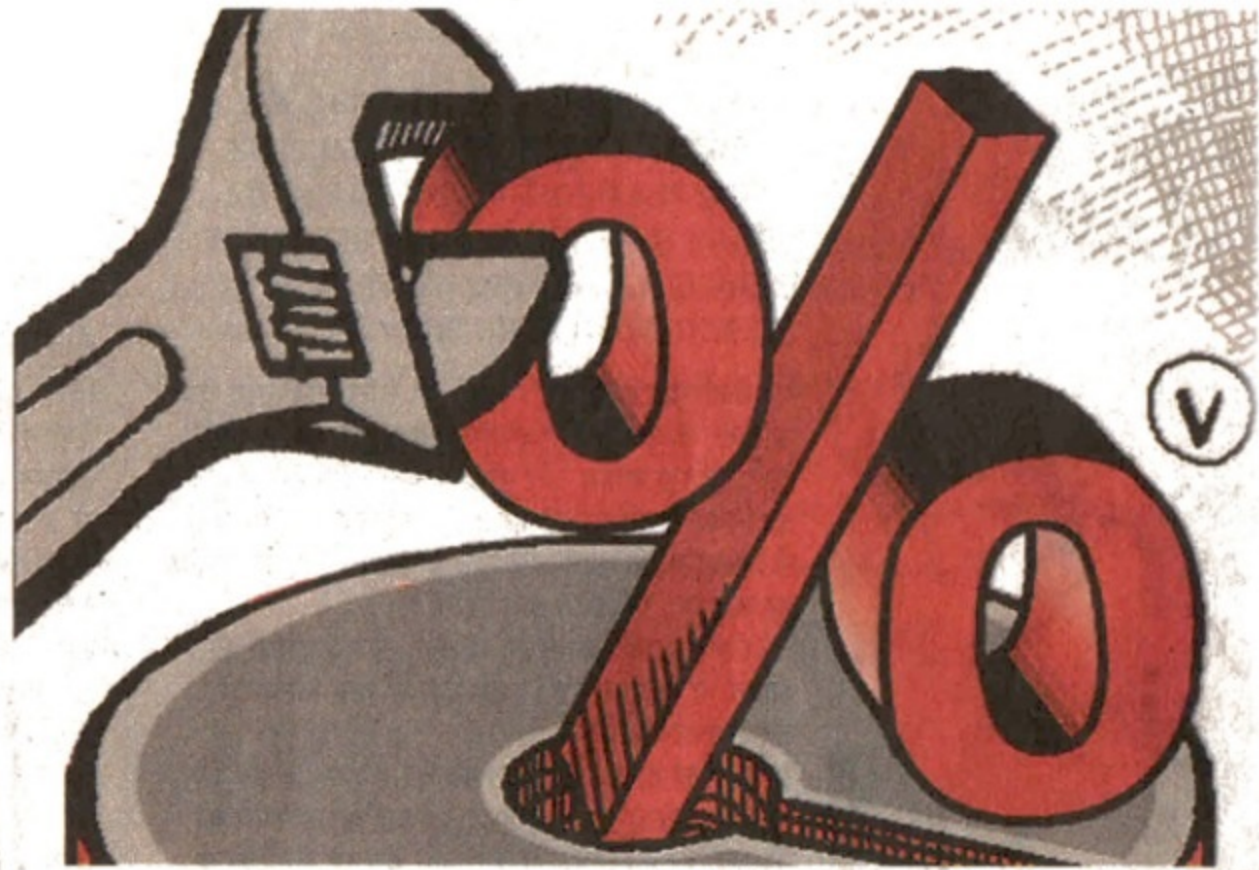
रेट कट से इंडस्ट्री निहाल, रियल्टर्स को दोहरी खुशी

रिजर्व बैंक के रुख में बदलाव से डिमांड और निवेश में तेजी की उम्मीद

[ईटी ब्यूरो | नई दिल्ली]

करीब डेढ़ साल बाद आरबीआई की ओर से रेपो रेट में की गई पहली कटौती इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव सरप्राइज के तौर पर आई है, जिससे कई सेक्टरों में उपभोक्ता डिमांड बढ़ने और निवेश में तेजी लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। खासकर अंतरिम बजट में इनकम टैक्स की सौगातों के तुरंत बाद हो रही इस कटौती से रियल एस्टेट सेक्टर उत्साहित है और उसने भरोसा जताया है कि यह सुस्ती से उबारने में बड़ी भूमिका निभाएगा।

सीआईआई के प्रेसिडेंट राकेश भारती मित्तल ने कहा कि रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती से कंप्यूशन और इनवेस्टमेंट दोनों मोर्चे पर डिमांड में तेजी लौटेगी। आरबीआई का रुझान ज्यादा सख्ती से तटस्थता की ओर शिफ्ट हुआ है, जिसका बिजनेस सेंटीमेंट सुधारने में मदद मिलेगी। फिक्की प्रेसिडेंट संदीप सोमानी कहा कि यह काफी मायने रखता है, क्योंकि फिलहाल इकनॉमी में जान फूंकने वाला कोई बाहरी कारक दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी सुस्ती से उबरने में जुटी है। ऐसे में डिमांड और निवेश बढ़ाने के लिहाज से यह सकारात्मक कदम है। एसोचैम की अफोर्डेबल हाउसिंग पर नेशनल कमेटी के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि यह कटौती न सिर्फ रियल एस्टेट और बड़े बायर्स, बल्कि उन घर खरीदारों के लिए भी लाभदायक होगी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ के हकदार हैं। यह कदम अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा। क्रेडाई के वाइस प्रेसिडेंट मनोज गौड़ ने उम्मीद जताई कि आरबीआई के इस कदम के बाद बैंक



- अंतरिम बजट में इनकम टैक्स की सौगातों के तुरंत बाद हो रही इस कटौती से रियल एस्टेट सेक्टर उत्साहित है
- RBI का रुझान ज्यादा सख्ती से तटस्थता की ओर शिफ्ट हुआ है, जिससे बिजनेस सेंटीमेंट सुधारने में मदद मिलेगी

भी रेट घटाएंगे। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स छूट की सीमा दोगुनी होने के बाद मिली यह राहत सेक्टर के लिए दोहरा प्रोत्साहन है। नाइट फ्रैंक के सीएमडी शिशिर बैजल ने कहा कि ग्राहक पर ईएमआई का बोझ घटने के साथ ही यह नए खरीदारों को प्रेरित करेगा और लंबे समय से मंदी

झेल रहे सेक्टर में नई जान फूकेगा। इससे रियल्टर्स में भी नए प्रोजेक्ट लाने का भरोसा जगेगा। नेशनल रियल एस्टेट डिवेलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट निरंजन हीरानंदानी सिर्फ इकनॉमी में लिक्विडिटी (कैश) नहीं बढ़ेगी बल्कि निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ऐनरॉक प्रॉपर्टीज के चेयरमैन अनुज पुरी ने कहा कि यह ओवर ड्यू था, क्योंकि अगस्त 2017 के बाद से कोई कटौती नहीं हुई थी। फियो के चेयरमैन गणेश गुप्ता ने कहा कि यह कटौती ऐसे समय हुई है जब एमएसएमई सेक्टर को क्रेडिट फ्लो अपने निचले स्तर पर है और बैंक रेट में नरमी से उन पर कर्ज का बोझ कम होगा। ईईपीसी के चेयरमैन रवि सहगल ने मांग की कि अब बैंकों पर दबाव डालना चाहिए कि वे इस कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाएं।